



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, वीरवार, ८ मई, १९९७/१८ बैशाख, १९१९

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग  
विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-१७१००२, ८ मई, १९९७

संख्या एल० एल० आर०-डी (६)-१२/९७-लेजिस.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद २०० के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक ७ मई, १९९७ को अनुमोदित उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, १९९७ (१९९७ का विधेयक संख्या १२) को १९९७ के

हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 14 के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,  
सचिव (बिबि)।

1997 का अधिनियम संख्यांक 14.

**उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 1997**

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 7 मई, 1997 को यथा अनुमोदित)

उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 5) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संक्षिप्त नाम संशोधन अधिनियम, 1997 है ।

1971 का 5 2. उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 की धारा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 5 का प्रतिस्थापन ।

“5. उप-मन्त्रियों के निवास स्थान.—(1) प्रत्येक उप-मन्त्री को, एक निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाएगा, जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा या ऐसे गृह के स्थान पर उसे दो हजार पांच सौ रुपये प्रति मास की दर से भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

(2) राज्य सरकार, उप-मन्त्री को दिए गए गृह का उसे, उसके उप-मन्त्री न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए, निःशुल्क अधिभोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

स्पष्टीकरण.—उप-मन्त्री ऐसे किसी मामले में जहां उसको आवास के लिए आबंटित गृह का मानक किराया उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक हो, किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा ।”

## AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 14 of 1997.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF DEPUTY MINISTERS  
(HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT ACT, 1997

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 7TH MAY, 1997)

-AN

## ACT

*further to amend the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 5 of 1971).*

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-eighth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 1997.

Substitution of section 5.

2. For section 5 of the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971, the following shall be substituted, namely:— 5 of 1971

“5. *Residence of Deputy Ministers.*—(1) Each Deputy Minister shall be provided with a free furnished house, the maintenance charges of which shall be borne by the State Government or in lieu of such house, shall be paid an allowance at the rate of two thousand and five hundred rupees per mensem.

(2) The State Government may allow a Deputy Minister to continue in free occupation of the house provided to him for a period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be a Deputy Minister.

*Explanation.*—The Deputy Minister shall not become liable personally for any payment in case the standard rent of the house allotted to him for residence exceeds the amount specified in sub-section (1).”